भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1442
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

इलैक्ट्रिक बसें

1442. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेट्रो शहरों में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए इलैक्ट्रिक बसें बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितनी इलैक्ट्रिक बसें बनाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार देश में हाइब्रीड/इलैक्ट्रिक बसों के निर्माण में तेजी लाने हेतु कुछ रियायतें देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : जी नहीं।

(ख) : शून्य। सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम इलेक्ट्रिक बस का विनिर्माण नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) : सरकार भी फेम इंडिया स्कीम के तहत, भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध इस स्कीम के अनुबंध 13 की तालिका 5 और तालिका 6 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार हाइब्रिड बसों के लिए मांग प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

*****